

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक,

कौशल किशोर,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/सचिव/सेटलर,  
राज्य के सभी निजी नर्सिंग स्कूल/संस्थान/कॉलेज, बिहार, पटना।

दिनांक: 07/01/2022

विषय: राज्य में संचालित निजी नर्सिंग संस्थानों में निर्धारित मानक के आलोक में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा के संबंध में।

महाशय,

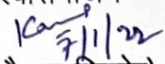
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा संस्थानों को अपना वेबसाईट तैयार करने, संस्थान में नामांकित/उत्तीर्ण वर्षवार प्रशिक्षणार्थियों, शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मी, स्कूल/संस्थान के संचालन ट्रस्ट/सोसाईटी का नाम, पूरा पता, दूरभाष संख्या, शैक्षणिक/छात्रावास भवन का फोटोग्राफ एवं विवरणी अपलोड करने का निदेश स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से दिया गया था।

2- विभिन्न संस्थानों द्वारा अपना वेबसाईट बना दिया गया है। किन्तु कई संस्थानों द्वारा अभी भी अपना वेबसाईट नहीं बनाया गया है और वांछित डाटा अपने वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। साथ ही राज्य में संचालित सभी नर्सिंग संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार हेतु समय-समय पर निर्धारित मानक के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता की जांच/सत्यापन आवश्यक है। इस संबंध में एक जनहित याचिका संख्या-13720/2021 धीरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया था।

3-वर्णितस्थिति में समादेश याचिका संख्या-13720/2021 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-03.08.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी से प्राप्त अभ्यावेदन (Representation) के आलोक में संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार एवं निर्धारित मानक के आलोक में इनके संचालन की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के सभी निजी नर्सिंग संस्थानों से Google form (जिसका लिंक है- [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmwNMcr6clx6CH8hHSBbGnXCqYSudvTa-h6T\\_zQnp29LeEmA/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmwNMcr6clx6CH8hHSBbGnXCqYSudvTa-h6T_zQnp29LeEmA/viewform?usp=sf_link)) में डाटा तैयार कर 5 दिनों के अन्दर (दिनांक-12.01.2022 तक) निश्चितरूपेण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

सभी संस्थानों को google form का लिंक ई-मेल के माध्यम से भी भेजा जा रहा है।  
उच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

  
(कौशल किशोर)

सरकार के अपर सचिव।